**भारत सरकार**

**जल शक्ति मंत्रालय**

**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3109**

**दिनांक 06 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ**

**.....**

**सिंचाई की स्थिति की समीक्षा**

**3109. श्री के. ई. प्रकाशः**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में भवानीसागर बांध से जुड़े जल भंडारण स्तरों और नहर आधुनिकीकरण कार्यों से उत्पन्न सिंचाई स्थिति की समीक्षा की है, जिससे विशेष रूप से ईरोड जिला प्रभावित हुआ है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भवानीसागर कमान क्षेत्र में नहर आधुनिकीकरण, सिंचाई अवसंरचना में सुधार या जल प्रबंधन में सहायता के लिए तमिलनाडु सरकार से कोई प्रस्ताव या अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने कलिंगरायन नहर और अन्य संबंधित सिंचाई नेटवर्क पर निर्भर किसानों पर सिंचाई के पानी को देर से छोड़े जाने के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रभावित कमान क्षेत्रों में सिंचाई बुनियादी ढांचे के समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने और जल-उपयोग दक्षता में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**

**(श्री राज भूषण चौधरी)**

**(क) से (घ):** जल, राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधन परियोजनाओं का नियोजन, वित्तपोषण, क्रियान्वयन, संचालन और रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों एवं प्राथमिकता के अनुसार स्वयं किया जाता है। भारत सरकार की भूमिका तकनीकी सहायता प्रदान करना और चल रही योजनाओं के अंतर्गत चिन्हित परियोजनाओं के लिए आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा तकनीकी जांच और उसके बाद जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर) की सलाहकार

समिति द्वारा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन, डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर की किसी भी योजना के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने वाली परियोजनाओं के लिए एक अनिवार्य शर्त है। भवानीसागर कमान क्षेत्र में नहर आधुनिकीकरण, सिंचाई अवसंरचना सुधार या जल प्रबंधन हेतु कोई भी प्रस्ताव, सीडब्ल्यूसी को मूल्यांकन के लिए प्राप्त नहीं हुआ है।

तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, लोअर भवानी परियोजना नहर प्रणाली, कोडिवेरी एनीकट सिंचाई प्रणाली और कलिंगरायन एनीकट नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण विस्तार, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण (ईआरएम) योजना के तहत नाबार्ड की सहायता से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, उनके द्वारा भवानीसागर बांध कमान क्षेत्र में सिंचाई की स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है। सिंचाई के अधिकतम लाभ को सुनिश्चित करने और साथ ही जल वितरण को समान रूप से बनाए रखने के लिए जल निकासी की योजना बनाई गई है।

भारत सरकार ने एक पायलट योजना लांच किया है, अर्थात - कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (एमसीएडी) का आधुनिकीकरण। इसका लक्ष्य कमान क्षेत्रों में जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने के लिए  भूमिगत दबावयुक्त पाइप सिंचाई द्वारा स्थापित स्रोत से लेकर खेत तक सूक्ष्म सिंचाई हेतु किसानों द्वारा मजबूत आधारभूत संरचना के साथ सिंचाई जल आपूर्ति नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना है। तमिलनाडु के तिरुप्पुर जिले में 4,989 हेक्टेयर की सीसीए के साथ एक परियोजना को एमसीएडी योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए शामिल किया गया है।

*****